

भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 390

मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020 को उत्तर के लिए नियत

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020

390. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

डॉ. सुजय विखे पाटील:

श्री हेमन्त पाटिल:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 का अनावरण फेम इंडिया स्कीम के हिस्से के रूप में 2013 में किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने सड़क परिवहन से प्रदूषण को कम करने और सभी प्रकार के वाहनों को कवर करने के लिए योजना में संशोधन किया है और यदि हां, तो इस संबंध में आवंटित राशि और उपयोग की गई राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) विनिर्माताओं को प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है और 31 अगस्त, 2020 तक लाभान्वित इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों की संख्या कितनी है;
- (घ) क्या सरकार ने हाल ही में फेम इंडिया योजना का दूसरा चरण शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) मल्टी-मॉडल इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रायोगिक परियोजना के लिए चुने गए शहरों की ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार ने 2017-18 के बाद से चार्जिंग बुनियादी ढांचे की प्रायोगिक परियोजना और तकनीकी विकास की परियोजना को मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (घ): नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं उनके विनिर्माण के लिए विजन तथा रोडमैप उपलब्ध कराने वाला एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज है। इस योजना को राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा में वृद्धि करने, किफायती एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन उपलब्ध कराने तथा वैश्विक विनिर्माण नेतृत्व प्राप्त करने के लिए भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

एनईएमएमपी 2020 के भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग ने देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मार्च, 2015 में एक योजना नामतः भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम-इंडिया) तैयार की। योजना का चरण-1 दिनांक 31 मार्च, 2019 तक उपलब्ध था। इस योजना के चार फोकस क्षेत्र नामतः मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजना, प्रौद्योगिकी विकास/अनुसंधान एवं विकास और चार्जिंग अवसंरचना थे।

इस योजना को नीचे दी गई अधिसूचनाओं के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया गया है:-

- अधिसूचना एसओ 2696(ई) दिनांक 30.08.2015 के द्वारा इस योजना को सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दुपहियों तथा तिपहियों को भारत में कहीं भी उनकी बिक्री करने हेतु लागू किया गया।
- अधिसूचना एसओ 4175 (ई) दिनांक 23.12.2016 के द्वारा तिपहियों (श्रेणी एल 5) के लिए योजना में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) श्रेणी को भी शामिल किया गया।
- अधिसूचना एसओ 2199 (ई) दिनांक 04.07.2017 के द्वारा इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (अधिकतम गति 25 किमी./घंटा से अधिक नहीं) को भी शामिल किया गया है।
- अधिसूचना एसओ 2198 (ई) दिनांक 12.07.2017 के द्वारा एल 5 श्रेणी को रेट्रो फिटमेंट श्रेणी में शामिल किया गया है।
- अधिसूचना एसओ 3012 (ई) दिनांक 12.09.2017 के द्वारा इस योजना के तहत मांग प्रोत्साहन के लिए पूर्णतः इलेक्ट्रिक बस को भी शामिल किया गया है।
- अधिसूचना एसओ 4994 (ई) दिनांक 27.09.2018 के द्वारा उन्नत बैटरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से पारंपरिक बैटरी वाहनों के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन के लाभों को बंद कर दिया गया।

फेम इंडिया योजना के चरण-1 के दौरान प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर और उद्योग एवं उद्योग संघों सहित सभी स्टेकहोल्डरों से परामर्श करने के बाद, सरकार ने दिनांक 08 मार्च, 2019 को फेम इंडिया योजना के चरण- II को अधिसूचित किया जो ₹10,000 करोड़ की कुल बजटीय सहायता के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से आरंभ होकर तीन वर्षों की अवधि के लिए है। यह चरण मुख्यतः सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण की सहायता करने पर केन्द्रित होगा, और मांग प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 7000 ई-बसों, 5

लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों की सहायता करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत चार्जिंग अवसंरचना के सृजन की भी सहायता की जाएगी।

फेम इंडिया योजना को कार्यान्वित करने हेतु बजटीय आवंटन और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन	उपयोग की गई निधि
1	2015-16	₹75 करोड़	₹75 करोड़ (लगभग)
2	2016-17	₹144 करोड़	₹144 करोड़ (लगभग)
3	2017-18	₹165 करोड़	₹165 करोड़ (लगभग)
4	2018-19	₹145 करोड़	₹145 करोड़ (लगभग)
5	2019-20	₹500 करोड़	₹500 करोड़ (लगभग)
6	2020-21	₹692.94 करोड़	31 अगस्त, 2020 के अनुसार ₹110.69 करोड़ (लगभग)

मांग सृजन के तहत, जोकि योजना का फोकस एरिया है, इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के खरीदार को एक्सईवी की खरीद के समय डीलर द्वारा खरीद मूल्य में अग्रिम छूट दी जाती है।

योजना के प्रथम चरण में लगभग ₹359 करोड़ के मांग प्रोत्साहन के द्वारा लगभग 2.8 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, भारी उद्योग विभाग ने लगभग ₹280 करोड़ की कुल लागत के साथ देश के अनेक शहरों को 425 इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड बसें मंजूर की। भारी उद्योग विभाग ने फेम इंडिया योजना के चरण-I के तहत ₹43 करोड़ (लगभग) के लिए लगभग 500 चार्जिंग स्टेशन/अवसंरचना मंजूर की।

फेम इंडिया योजना के चरण-II के तहत, लगभग ₹95 करोड़ के मांग प्रोत्साहन के द्वारा दिनांक 10.09.2020 तक 27,201 इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, योजना के चरण-II के तहत अनेक राज्य/नगर परिवहन उपक्रमों को 5595 इलेक्ट्रिक बसें मंजूर की गई हैं। इसमें लगभग ₹2800 करोड़ का सरकारी प्रोत्साहन शामिल है।

भारी उद्योग विभाग ने फेम इंडिया (भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण) योजना के चरण-II के तहत 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 62 नगरों में ₹500 करोड़ (लगभग) से 2,636 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन भी मंजूर किए हैं।

(ड): मल्टी मॉडल इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन की प्रायोगिक परियोजना के लिए चुने गए और निधि प्राप्त करने वाले शहरों का ब्यौरा अनुबंध-I में है।

(च): जी, हां। फेम इंडिया योजना के चरण-I के तहत चार्जिंग अवसंरचना की प्रायोगिक परियोजना और प्रौद्योगिकी विकास परियोजना की सूची अनुबंध-II पर है।

अनुबंध-I

इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड सार्वजनिक परिवहन की प्रायोगिक परियोजना के लिए वित्तपोषित किए जा रहे और चुने गए शहरों का ब्यौरा।

क्रम सं.	शहर	बसें
1	मुम्बई	40
2	नवी मुम्बई	30
3	एमएमआरडीए	25
4	लखनऊ	40
5	हैदराबाद	40
6	इंदौर	40
7	कोलकाता	80
8	जम्मू	40
9	गुवाहाटी	15
10	हिमाचल प्रदेश	75
	कुल	425

**फेम इंडिया स्कीम के तहत भारी उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं
(प्रायोगिक परियोजनाएं, चार्जिंग अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास)**

क्रम सं.	परियोजना का नाम	संचालित करने वाली एजेंसी का नाम
1	बैंगलोर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक तीव्र चार्जिंग अवसंरचना नेटवर्क।	लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजिज प्रा. लि. के सहयोग से मेसर्स महिंद्रा रेवा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रा. लि.
2	एआरएआई पुणे में इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों के परीक्षण के प्रमाणन हेतु परीक्षण अवसंरचना की स्थापना।	भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ (एआरएआई)
3	एक्सईवी चार्जिंग स्टेशनों, एआरएआई, पुणे के मसौदा मानकों के विशिष्टिकरण एवं अंतिम रूप देने हेतु प्रस्ताव।	भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ (एआरएआई)
4	चार्जिंग अवसंरचना प्रबंधन प्रणाली हेतु प्रस्ताव, आईआईटी मद्रास	आईआईटी मद्रास
5	ब्रांद्रा कुर्ला परिसर के लिए 25 हाइब्रिड बसों हेतु प्रस्ताव, एमएमआरडीए मुम्बई	मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)
6	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 25 इलेक्ट्रिक बसों हेतु प्रस्ताव।	हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम (एचआरटीसी)
7	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय परिवहन हेतु 50 मैक्सी केब हेतु प्रस्ताव।	हिमाचल प्रदेश नगर परिवहन एवं बस स्टेड प्रबंधन और विकास प्राधिकरण (एसपीसीटी और बीएसएम और डीए)
8	आरईआईएल, जयपुर द्वारा एनसीआर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सौर आधारित चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने हेतु प्रस्ताव।	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लि. (आरईआईएल), जयपुर
9	बीएचईएल द्वारा उद्योग भवन के प्रांगण में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सौर आधारित चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने हेतु प्रस्ताव।	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल)
10	इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उन्नत जेन-IV लेड एसिड बैटरी और जेन-निकल-जिंक बैटरी हेतु तकनीकी विकास परियोजना।	नॉन फेरॉस मेटेरियल्स टेक्नोलॉजी डब्लपमेंट सेंटर (एनएफटीडीसी), हैदराबाद
11	अगरतला में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण	भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीआई)

	के लिए 2 इलेक्ट्रिक वाहनों (5-7 सीटर) हेतु प्रस्ताव।	
12	एएमयू में विद्युतीकृत परिवहन में उन्नत अनुसंधान हेतु प्रस्ताव।	अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी (एएमयू)
13	बैटरी इंजीनियरिंग केन्द्र हेतु प्रस्ताव	आईआईटी मद्रास
14	ऑटोमोटिव बैटरियों और सुपर कापासिटर्स हेतु उच्च दर एवं कार्यनिष्पादन के लिए कैंडल सूट ग्रेफाइन से जनित हिराचिकल कार्बन मटेरियल्स के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की आईएमपीआरआईएनटी पहल के तहत प्राप्त प्रस्ताव।	आईआईटी कानपुर
15	अक्षय ऊर्जा आधारित ईंधन सेल रेंज एक्सटेंडर के साथ हल्के वजन वाले आरईईवी के ऑटोमोबाइल क्षेत्र-विकास से संबंधित यूएवाई परियोजना हेतु वित्तीय सहायता।	आईआईटी मद्रास
16	आरईआईएल, जयपुर द्वारा 200 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु प्रस्ताव।	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लि. (आरईआईएल), जयपुर
17	एआरएआई द्वारा एसी-डीसी दोनों सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का डिजाइन एवं विकास	भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ (एआरएआई)
18	ईवी बस के लिए डीसी चार्जिंग हेतु प्रायोगिक प्रौद्योगिकी।	<u>प्रधान जांचकर्ता</u> पनवा इंजीनियरिंग प्रा. लि., नासिक, महाराष्ट्र <u>सह-प्रधान जांचकर्ता</u> के.के. वाघ इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, नासिक, महाराष्ट्र
19	आईसीटी समर्थ स्मार्ट चार्जिंग नेटवर्क घटकों का विकास एवं प्रोटोटाइपिंग	<u>प्रधान जांचकर्ता</u> आईआईटी दिल्ली <u>सह-प्रधान जांचकर्ता</u> थापर युनिवर्सिटी, अमृता विश्व विद्यापीठम्, लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजिज <u>उद्योग भागीदार</u> इलैक्सिस टेक्नोलॉजिज प्रा. लि., इंजी.(जीडीएफ सुएज एनर्जी), लिंकवेल टेलीसिस्टमस, येक्सक्यूब टेक्नोलॉजीज

20	ई-दुपहिया और ई-तिपहिया इलेक्ट्रिक ड्राइव हेतु हब एवं स्पोक कंसोर्टियम।	<u>प्रधान जांचकर्ता</u> टीवीएस-लुकास लि., एनएफटीडीसी, हैदराबाद संस्थाएं आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी बीबीएसआर, वीआईटी चेन्नई, एनआईटीटीईई सुरतकल <u>उद्योग भागीदार</u> लुकास टीवीएस, चेन्नई, एम्पियर व्हीकल्स, कोयम्बतूर, इलेक्ट्रोथर्म, लोहिया ऑटो इंडस्ट्रिज
21	दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए स्विचड रिलेक्टेड ट्रेक्शन मोटर एवं कंट्रोलर।	<u>प्रधान जांच</u> आदित्य ऑटो प्रोडक्ट्स एंड इंजी. (आई) प्रा. लि. एनआईटीके सुरतकल <u>उद्योग भागीदार</u> हीरो इको, एम्पियर व्हीकल्स प्रा. लि.
22	भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन अनुप्रयोगों हेतु सिंक्रोनस रिलेक्टेड मोटर ड्राइव	<u>प्रधान जांच</u> आईआईटी मद्रास <u>उद्योग भागीदार</u> महिंद्रा रेवा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लि., बेंगलुरु
23	30 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद	नवी मुम्बई म्यूनिसिपल परिवहन (एनएमएमटी)
24	सौर ग्रिड हाइब्रिड और ग्रिड से चलने वाले चार्जिंग स्टेशन (270 चार्जर)	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लि. (आरईआईएल), जयपुर
25	नेट्रिप से ईवी और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) कार्यानिष्पादन परीक्षण/प्रमाणन के लिए परीक्षण सुविधा अवसंरचना हेतु अनुदान सहायता हेतु प्रस्ताव।	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप)
26	सौर आधारित ईवी चार्जर्स की स्थापना	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल)
